मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

हूडा का ऑनलाइन सिस्टम फेल, ग्राहक परेशान 2
यह है मनोहर की मनोहारी नगरिया तू देख बबुआ 4
'ऐतिहासिक किसान आन्दोलन' की जीत की याद में.... 5
निर्णायक संघर्ष की ओर 6
घोषणावीर खट्टर, जुमलों की बरसात, काम का सूखा 8

वर्ष 37 | अंक 2 | फरीदाबाद | 27 नवम्बर -03 दिसम्बर 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, इलाज 'आयुष्मान' से!

फ़रीदाबाद (म.मो.) काम करना नहीं परन्तु काम करने का ढोंग जरूर करना है। किसी भी अच्छे प्रचारक की भांति यही खूबी संघ प्रशिक्षित मुख्यमंत्री खट्टर की है।

बीते सप्ताह खट्टर जी 'टेलीमेडिसिन' के द्वारा जनता को चिकित्सा सेवायें प्रदान करने की घोषणा कर रहे थे। इस सप्ताह मानेसर में भाषण देते हुए उन्होंने 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से राज्य की जनता को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का ढोल पीटा। वैसे ये कोई नया ढोल नहीं पीट रहे हैं। जुमलेबाज मोदी द्वारा 2018 में दिये गये इस ढोल को खट्टर सहित तमाम मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में पीट रहे हैं। यह, वह समय था जब 2019 के लोकसभा चुनाव सिर पर थे। उस वक्त तक न तो मोदी सरकार ने और न ही खट्टर सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम किया था। हां, अनेकों एम्स व मेडिकल कॉलेजों की घोषणायें जरूर कर रखी थीं जो आज तक भी घोषणायें ही हैं। इन हालात में जनता को बेवकूफ बनाकर वोट बटोरने के लिये 'आयुष्मान भारत' का जुमला ईजाद किया गया था।

अब डेढ़ साल बाद फ़िर चुनाव आने वाले हैं, इसलिये 'टेलिमेडिसिन' के साथ-साथ 'आयुष्मान भारत' का ढोल पीटा जा रहा है। 'आयुष्मान भारत' के लाभार्थियों का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को रखा गया है। इसके लिये अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रखी गई है। इसके आधार पर खट्टर सरकार ने 13 लाख लोगों को कार्ड बांट दिये हैं। केन्द्र सरकार की इस योजना में 60 प्रतिशत खर्च केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसके अलावा खट्टर सरकार ने अपनी ओर से लाभार्थियों की आय सीमा 1 लाख 80 हजार कर दी है। इस वर्ग में 15 लाख अतिरिक्त कार्ड बने बताये जा रहे हैं। इन बढे हुए कार्डों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

इस पाखंड योजना के बारे में पहले भी कई बार लिखा जा चुका है कि घर के हर सदस्य के लिये अलग-अलग कार्ड बनवाना अनिवार्य है। लेकिन एक परिवार के कुल खर्च की सीमा पांच लाख रखी गई है। इस योजना में इतने घुमावदार पेच रखे गए हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई बिरला ही इसका लाभ उठा सके। इलाज के रेट इतने कम रखे गये हैं कि लगभग तमाम बड़े व्यापारिक अस्पतालों ने इस योजना को लेने से इन्कार कर दिया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ़रीदाबाद में उद्घाटित अम्मा के अस्पताल ने भी इस योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है। साधारण डिलिवरी के लिये 9000 तथा सिजेरियन के लिये 13000 रुपये तय किये गये हैं। सर्वविदित है कि इतने-इतने पैसे तो सरकारी अस्पतालों में रिश्वत के तौर पर ही वसूल लिये जाते हैं। व्यापारिक अस्पताल भला इन दामों में किसी मरीज़ को कैसे घुसने दे सकते हैं? वैसे भी सरकार ने इस तरह के मरीजों के लिये अपने सरकारी अस्पतालों को ही अधिसूचित तो कर रखा है, लेकिन सम्बन्धित बीमारियों की कोई सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

हृदय सम्बन्धित गंभीर रोगों तथा ऐसे ही कुछ अन्य रोगों के लिये ही व्यापारिक अस्पतालों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हृदय रोग के लिये व्यापारिक अस्पताल दो से तीन लाख तक वसूल लेते हैं, उसके लिये इस योजना के तहत मात्र 60 हजार रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में भला कोई भी चिकित्सा व्यापारी इतना बड़ा घाटा कैसे उठा लेगा? इन दामों में तो बीके अस्पताल में चल रही हृदय रोग की दुकान भी इलाज करने को तैयार नहीं।

तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत सुधी पाठकों से छिपी नहीं है। जिस बादशाहखान की दुर्दशा स्थानीय जनता देख रही है, शेष अस्पतालों की हालत तो

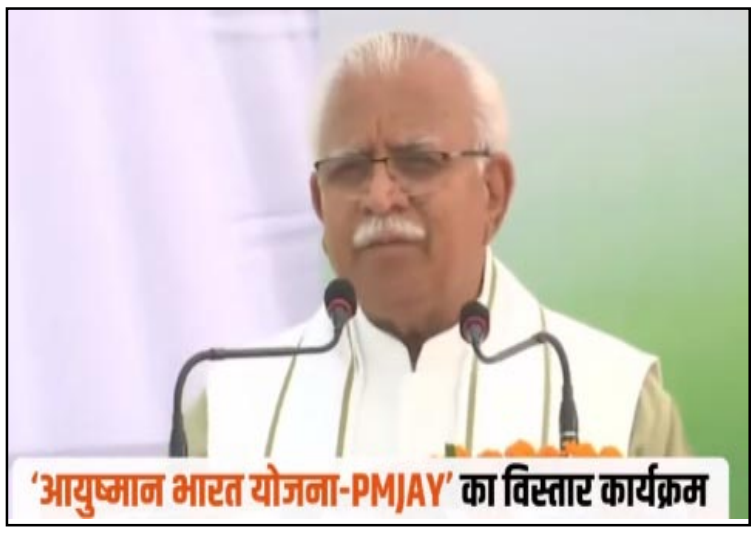

इससे भी गई-बीती है। समझना कठिन नहीं है कि इन सरकारी अस्पतालों में 'आयुष्मान कार्ड' अपनी क्या ऐसी-तैसी करायेगा? गौरतलब है कि इन अस्पतालों में इस कार्ड के बगैर भी आने वाले मरीजों की बड़ी भारी संख्या है। खट्टर जी ने कार्ड बनाने की आय सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये रखी है, ऐसे में 1 लाख 81 हजार या दो लाख वार्षिक आय वाले 'अमीर' कहां जायेंगे? जाहिर है ये सब भी इन्ही सरकारी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। समझा जा सकता है कि ऐसे में यह कार्डनुमा झुनझुना किसी को क्या दिला पायेगा?

असल काम जो करने का है, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में स्टाफ़ बढाने का, जिसे न करने की कसम सरकार ने खा रखी है। हरियाणा सरकार का कोई भी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र ऐसा नहीं है कि जिसमें आधे से अधिक पद रिक्त न हों। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 30-35 प्रतिशत

शेष पेज दो पर

'सामाजिक न्याय एवं अधिकार संगठन' ने विफल किया धार्मिक उन्माद भड़काने का षड़यंत्र

फरीदाबाद (म.मो.) प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र नीलम बाटा रोड के डिवाईडर पर कोतवाली के लगभग सामने एक छोटी सी बहुत पुरानी मज़ार है। कुछ दिन से कुख्यात हिन्दुत्ववादी उन्मादी बिट्टू बजरंगी के नेतृत्व में उस मज़ार को चारों ओर से घेरकर, हिन्दुत्ववादी उन्मादियों की टोली हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी है.

इस मजार को शहर का माहौल ख़राब करने का ज़रिया बनाया जा रहा है. बेहाल-बेरोज़गार लोगों, ख़ासतौर पर मज़दूरों को हिन्दू-मुस्लिम करने का प्रपंच रचा जा रहा है. इस ज़हरीले उपक्रम को इसी स्तर

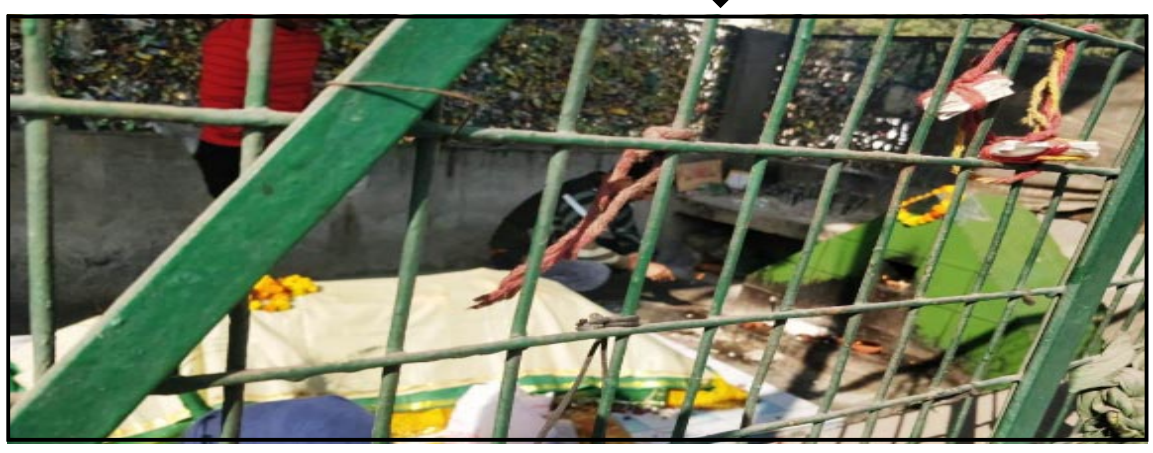

पर रोकना, हर जागरुक नागरिक का फ़र्ज़ है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं 'सामाजिक न्याय एवं अधिकार संगठन' के अध्यक्ष साथी दीनदयाल गौतम ने, बिट्टू बजरंगी की इस घिनौनी, माहौल ख़राब करने वाली करतूत के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज़ कराई है.

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोर्चा साथी दीनदयाल गौतम द्वारा उठाए गए इस क़दम की सराहना करता है और उन्हें आश्वस्त करना चाहता है कि हम इस संघर्ष में पूरी शिद्दत से उनके साथ हैं. वातावरण दूषित

शेष पेज दो पर